भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1127
दिनांक 05.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निधि का आवंटन

†1127. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 31-03-2024 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग को लगभग 22,500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या विभाग ने केन्द्रीय बजट 2024-25 में मांग संख्या 63 के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 70,000 करोड़ रुपये का कुल आवंटन मांगा था;
(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत अनुदान मांगों में शामिल किए जाने से पूर्व इस अतिरिक्त राशि को केन्द्र सरकार के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो आवंटन के लिए मांगी गई राशि और आबंटन हेतु विधिवत स्वीकृत और उपलब्ध कराई गई राशि के बीच अंतर के क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए, भारत सरकार, राज्यों की भागीदारी से, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जेजेएम के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, देश में केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल

जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 12.59 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 28.01.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.79 करोड़ (81.57%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

अगस्त 2019 में, मंत्रिमंडल ने 2,08,652 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 2019-20 से 2023-24 तक जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। विभाग ने 2023-24 तक 1,85,958 करोड़ रुपये का उपयोग किया था, जिससे 2023-24 के बाद उपयोग हेतु 22,694 करोड़ रुपये शेष रह गए थे।

(ख) और (ग): प्राप्त प्रगति, जारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए और जल जीवन मिशन को 2023-24 के बाद भी संवर्धित परिव्यय के साथ जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी के पूर्वानुमान में, 2024-25 के लिए बजट अनुमान के रूप में 70,162.90 करोड़ रुपये की राशि पर विचार किया गया था।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****